



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक : 425 / मान0अनु0 / जोन-बी / 2020

दिनांक 28-5-2020

श्री अनुराग अग्रवाल पुत्र श्री हरिओम अग्रवाल,
निवासी-184बी, आबूलेन,
मेरठ कैण्ट।

सम्बन्धित

आपके द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2019 को स्वीकृत मानचित्र सं0-MAP20180322164355480 को संशोधित किये जाने का अनुरोध के क्रम में ग्राम सलारपुर जलालपुर, मेरठ के खसरा सं0-279, 280, 335, 336, 338, 339, 340, 341पार्ट से 344, 346 से 350, 352पार्ट व 353 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक 21.03.2020 को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 के अधीन दण्डनीय है।
4. पत्रांक 2396/मान0अनु0/जोन-बी/19 दिनांक 24.06.2019 में निर्धारित की गयी किशतों को निर्धारित समय पर जमा कराना होगा।
5. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्तियों में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
6. रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का प्राविधान भवन की फिनिशिंग के कार्य से पहले पूर्ण करना होगा।
7. इन्डीविजुअल भूखण्डों के भवन मानचित्र पृथक-पृथक तत्समय प्रभावी भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत कराकर ही भवन निर्माण किया जा सकेगा।
8. नियमानुसार प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा इसके उपरान्त ही अध्यासन किया जायेगा।
9. सम्पूर्ण विकास कार्य के उपरान्त सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नगर निगम को अपने व्यय पर हस्तांतरित करना होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं का होगा। प्रस्तावित विन्यास क्षेत्र का अनुरक्षण स्वयं द्वारा तब तक किया जाता रहेगा जब तक उसे नगर निगम को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता।
10. स्थल पर मानचित्र में दर्शित 15 प्रतिशत पार्क क्षेत्र को ग्रीन के रूप में ही उपयोग में लाया जायेगा।
11. आन्तरिक विकास कार्य यथा-इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ जैसे-सड़क, सीवर, सीवर डिस्पोजल, ड्रेन, ड्रेन डिस्पोजल, पीने के पानी की व्यवस्था एवं सोलिड वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।
12. समस्त प्रकार के निर्माण/विकास कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण की विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप आर्किटेक्ट/इंजीनियर की देखरेख में कराने होंगे तथा शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण कराना होगा।
13. भू-गर्भ जल उपयोग किये जाने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति स्वयं प्राप्त करना होगा, तथा सम्बन्धित विभाग से विवाद या आपत्ति होने की स्थिति में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
14. प्राधिकरण के साथ किये गये अनुबन्ध एवं शपथ पत्रों में अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
15. कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
16. विद्युत व्यवस्था हेतु उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन से स्वयं कनेक्शन प्राप्त करना होगा।
17. मानचित्र स्वीकृति भू-स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू-स्वामित्व सम्बन्धी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में स्वयं उत्तरदायी होगा।

18. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में कोई बड़ा हुआ विकास शुल्क या अन्य किसी शुल्क की मांग की जाती तो स्वयं जमा करना होगा।
19. सड़को के जंक्शन पर फायर हाईड्रेन्ट लगाने होंगे।
20. स्वीकृत तलपट मानचित्र का डिस्पले स्थल पर करना होगा।
21. विभिन्न मदों में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही मान्य होगी।
22. भविष्य में आवंटियों एवं स्वयं के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद का दायित्व स्वयं का होगा।
23. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या 21/2014/ में अलग अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1760/पी0एस0एम0एस0/2016 दिनांक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ-5-206-29रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 1. Owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including owner, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
 2. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
 3. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
 4. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
 5. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
 6. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
 7. Owner shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
 8. It shall be the responsibility of owner to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
 9. All owners/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
 10. Wind breaking walls around constructin site.
 11. All owners shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the owners and transporters.
 12. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
 13. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
 14. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
 15. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
 16. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
 17. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

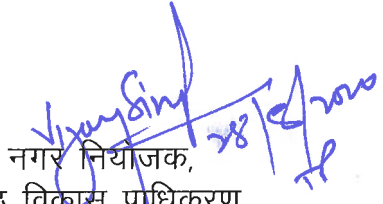
18. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
19. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
20. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
21. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
22. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.16 में उल्लेखित धनराशि पैनल्टी के रूप में वसूल की जायेगी।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता प्रवर्तन, जोन-क्षेत्रीय को प्रेषित।


नगर नियाजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।